

Symbiosis Law School Pune

NATIONAL VIRTUAL DISCUSSION CUM PUBLIC CONSULTATION ON TRANSFORMATION OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA INITIATIVE

News clipping and news published online in Pune, Mumbai, Maharashtra, Bangalore,
Mangalore and other state's web portal.

1. Lokmat News Network:

**शिक्षेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी
अमेरिकन तपास पध्दत हवी**

ॲड. उज्ज्वल निकम, सिंबायोसिस विद्यापीठात चर्चासत्र

लोकमत ब्यूज नेटवर्क

पुणे: गुन्हांबद्दल शिक्षेचे प्रमाण वाढावे, यासाठी अमेरिकन तपास पध्दतीचा अवलंब करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी केले.

फौजदारी कायद्याचा आढावा घेत त्यातील लोकाभिमुख बदलावाबद सोमवारी (ता. १९) दुपारी ॲनलाइन चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या सिंबायोसिस विधी महाविद्यालयाने या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. त्यावेळी निकम बोलत होते.

चर्चासत्रात न्या. शालिनी फणसळकर जोशी, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. एस. के. जैन, टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे डॉ. अरविद तिवारी, माझी कुलपती डॉ. एस. सी. रेना, मनोविकार तज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्री,

सरकारी वकिलांचे सहकार्य

ॲड. निकम म्हणाले, अमेरिकेत गुन्हा घडल्यानंतर पोलिस तपास सुरु असतानाच सरकारी वकील त्याना सहकार्य करतात. त्यामुळे आरोपपत्र दाखल करताना कोणतीही त्रुटी रहात नाही. परिणामी गुन्हेगाराला कायद्यातील पळवाटांचा फायदा होत नाही आणि शिक्षेचे प्रमाण वाढते. याउलट आपल्याकडे होते परिणामी गुन्हेगार कायद्यातील पळवाटा शोधून नियोग सुटतात आणि शिक्षेचे प्रमाण घटते. वरीष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यानीही वेळोवेळी तपासाकडे लक्ष दिले पाहिजे.

सुनावणी दरम्यान बदली नको

ॲड. जैन म्हणाले, महत्वाच्या गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली सुनावणी दरम्यान करू नये. तसे झाल्यास तपासी अधिकारी आणि सरकारी वकील याच्यामध्ये समन्वय साधून साक्षीदाराने नेमके काय सांगायचे आहे, गुन्ह्याचा तपास नेमका कसा केला याची सदिस्तर माहिती मिळाल्याने गुन्हा सिद्ध हाण्यास मदत होते.

यांनी चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन केले. चर्चासत्राद्वारे तज्ज्ञांकडून आलेल्या सूचना व ॲनलाइन मतदानाच्या आधारे आलेले प्रतिसाद, केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पाठविण्यात येणार आहे.



राजुरा यथारु अपघातात दावाचा भूत्पू

आलेफाटा : राजुरी (ता. जुन्नर) येथे आज (ता. १८) सायंकाळी कल्याण - नगर महामार्गवर एस.टी. व दुचाकी यांच्यात धडक होऊन झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील २ जण जागीच ठार झाले. राजुरी येथे श्रीराम मंगल कार्यालयासमोर कल्याण - नगर महामार्गवरुन नगर बाजूकडून कल्याणकडे येणारी एस.टी. बसगाडी व कल्याणकडून नगरकडे जाणारी दुचाकी यांच्यात धडक होऊन हा अपघात झाला. यात दुचाकीवरील दोघे तरुण जागेवरच ठार झाले. या मृतपैकी एक जण बेल्हे येथील रहिवासी आहे. दरम्यान, पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक सचिन डौले करीत आहेत.

कायद्यातील बदलांबाबत आज चर्चासत्र

पुणे : फौजदारी कायद्याचा आढावा घेत त्यातील लोकाभिमुख बदलांबाबत सोमवारी (ता. १९) दुपारी तीन वाजता ऑनलाईन चर्चासत्र आयोजित केले आहे. सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या सिम्बायोसिस विधी महाविद्यालयाने (एसएलएस) या चर्चासत्राचे आयोजन केले आहे. चर्चासत्रात विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, ॲड. सतीश माने-शिंदे, ॲड. हितेश जैन, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे डॉ. अरविंद तिवारी, माजी कुलपती डॉ. एस. सी. रैना, मनोविकार तज्ज्ञ डॉ. हरीश शेष्ठी आणि समाजशास्त्र तज्ज्ञ डॉ. डी. पी. सिंग आदी तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. चर्चासत्रात सहभागी होण्यासाठी director@symlaw.ac.in या मेल आयडीवर संपर्क करावा.

केन्द्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी-पुणे सामग्री एवं सेवा आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण हेतु विज्ञापन (Vendor Registration for KV NDA, Pune)

केन्द्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, पुणे विद्यालय में उपयोग आनेवाली विभिन्न सामग्री एवं सेवाएं प्रदान करने हेतु विश्वसनीय प्रतिष्ठानांकों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। विद्यालय को आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों एवं सेवाओं का विवरण निम्नलिखित है-

प्रयोगशाला सामग्री (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित) (Laboratory Equipments), खेलकूद सामग्री (Sports Material), कार्यालयी लेखन सामग्री (Office Stationary materials), गृह रख-रखाव एवं संरक्षण सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं

‘भारतीय फौजदारी न्याय प्रणाली में परिवर्तन’ विषय पर चर्चा-सत्र

सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज द्वारा ऑनलाइन आयोजन : कानून की समीक्षा करने की प्रक्रिया

विभागनगर, 21 अक्टूबर (आ.प.)

सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज द्वारा भारतीय फौजदारी न्याय प्रणाली के परिवर्तन के विषय पर ऑनलाइन चर्चा-सत्र का आयोजन किया गया है। मंगलवार (19 अक्टूबर) की दोपहर २:०० बजासात में छह विषयों पर चर्चा की गई। इनमें न्यायाधीश, सरकारी बक्सल, शिक्षा विशेषज्ञ, पुलिस, ऐस-सरकारी संस्था, प्रसार माध्यमों और कानूनी अधिकारीयों के माध्यम से अधिक विशेषज्ञ शामिल हुए।

प्रमुख रूप से दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया सहित, इंडियन इवीडेंस एन्ट और एटी बारकाइव्स एक्ट में आम लोगों की आर्थिक दृष्टि से संस्ते और लोकाभिमुख बदलाव करने की ज़रूरत है, इसी उद्देश्य से कानून में बदलाव करने की तैयारी शुरू है। इसके महेवर बह ऑनलाइन चर्चा-सत्र हुआ।

इसमें विशेष सरकारी बक्सल उच्चाला निकम, एड. एस. के. जैन, एड. मर्टिन मानेसिंह, एड. हिंदें जैन, टिटान डूलिस अधिकारी भानुप्रताप बर्गे और

चर्चासत्र में रखे गए कई महत्वपूर्ण विद्

- ✓ जब लिंगटम और सरकारी बक्सलों के बीच समन्वय का अनाव
- ✓ मौदिया में यात्रा जाने से बैत पर पहने बाल परिणाम व इसे रोकने के लिए केस बनने की कार्रवाई का उपय
- ✓ गवाहों के साथ सम्बन्धनक व्यवहार की ज़रूरत है, गवाहों को भावनात्मक सुरक्षा देना आवश्यक है, गवाहों के मानवाधिकार सुनिश्चित रखने के लिए जनजागृति पर अधिक जोर दिया जाए
- ✓ सीआरपीसी की धारा 258 के अनुसार आवेदन देने पर कोर्ट के कानूनकान की ज़रूर से देरी और अंक ट्रायल केडिंगों की प्राधिकारी समस्या कम हो सकती है
- ✓ साझबर फौरेसिक लैंब की तीव्रता कम है

कानून में परिवर्तन लाना केंद्र का उद्देश्य

फौजदारी कानून में परिवर्तन लाना केंद्र सरकार वा उद्देश्य है, इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुणे के सिम्बायोसिस लॉक स्कूल लॉ को आमंत्रित किया है। इसकी प्रक्रिया के एक भाग के स्वरूप में चर्चा-सत्र से इस विषय की समीक्षा करके फौजदारी कानून की कमियों को समझा गया। तब विषयों के अनुसार सिम्बायोसिस की टीम द्वारा युजाए गए विकारिश की समीक्षा की गई, हर विषय के बाद ऑनलाइन प्रश्नावली भेजकर इस पर ऑनलाइन राय ली गई।

प्रकाश रोहित आठवें, मुंबई हाईकोर्ट की जज डॉ. जालिमी फणसालकर जाजी, पर.ए.एल.एस.ए. में बदलाव और पालिमी सत्राहकार असोक अग्रवाल, एड. लियका सत्राहकार, मोर्चिकितमज्ज डॉ. हरीश नेटटी, केआईआईटी भवेनकर के हायरेक्टर डॉ. पर. सी. रेना, पर.ए.एल.एस.ए. के डायरेक्टर सुनील चौहान, आईआरएस निति कोडावल पाटिल, टीआईएसएस में समाजसाम्बन्ध डॉ. पी. सिंह, एड. संपत कुलमु, शेल हजोरा,

एल.एन.जी. डॉ. अरविंद तिवारी, माइक्रोफोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. हीरोल्ड डीकोस्टा आदि शामिल हुए थे।

इस ऑनलाइन चर्चा-सत्र में प्रमुख कानून से चुनिस अधिकारियों व सरकारी बक्सलों में सम्बन्ध रखने वाले कानून में अर्थात बड़ोत्तरी, गवाहों की सुरक्षा, केस हटाने के प्रावधान का गलत इस्तेमाल, माइक्रो एड. कार्यसिक, फिलहाल जेल से छोड़ने के मूल पर चर्चा की गई।

विभिन्न पैनल से घोड़ेशन सिम्बायोसिस

अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉप मूविंसिंस्टी के सर्विसेट की डायरेक्टर और डॉ. डॉ. जालिमी गृह से किया। जबकि उनके महामंत्रीजक के कानून में डॉ. आमारप शेख, एड. सदामर्जित बलवान, प्रोफेसर चैतानी देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. योहान देशपांडे और असिस्टेंट प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी ने सहयोग किया, प्रोफेसर लक्ष्मा व्याकरण ने कार्यक्रम का मूल-संचालन किया। जबकि उपमंत्रियों की ओर से डॉ. रोनाल्ड ने आभार जताया।

4. Media Bulletins - <http://mediabulletins.com/business-world/virtual-panel-discussion-cum-public-consultation-on-transformation-of-the-criminal-justice-system-in-india-ministry-of-home-affairs-government-of-india-initiative/>

[Business World](#)

Virtual Panel Discussion Cum Public Consultation on Transformation of The Criminal Justice System In India Ministry of Home Affairs, Government of India Initiative

6 days ago Pariti. Gayathri



[fb Like](#) [Twitter](#) [Save](#) [Share](#) [In Share](#)

Symbiosis Law School Pune, a constituent of Symbiosis International (Deemed University), hosted a Panel Discussion cum Public Consultation cum Public Consultation on 'Transformation of Criminal Justice System in India'. The 'virtual Panel Discussion cum Public Consultation' was conducted on 19 October, 2020, from 3:00 pm to 7:30 pm.

The Government of India aims to make fundamental changes to the Indian Criminal Law framework and Criminal Justice System, in order to make it more accessible, affordable and citizen centric. The Minister of Home Affairs, Government of India has therefore invited Symbiosis Law

5. The New Biz - <https://thenewzbiz.com/?p=3345>

BUSINESS EVENTS LATEST NEWS

VIRTUAL PANEL DISCUSSION CUM PUBLIC CONSULTATION ON TRANSFORMATION OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA INITIATIVE

Share this Newsz

5 days ago



The image shows a 4x4 grid of 16 video feeds, each displaying a different person's face. The participants appear to be diverse in terms of gender and ethnicity, and some are wearing masks. The background of each feed varies, showing different indoor settings like offices or homes.

Share this Newsz



The Newz Biz Team, Pune

Symbiosis Law School Pune, a constituent of Symbiosis International (Deemed University), hosted a Panel Discussion cum Public Consultation cum Public Consultation on 'Transformation of Criminal Justice System in India'.

The Government of India aims to make fundamental changes to the Indian Criminal Law framework and Criminal Justice System, in order to make it more accessible, affordable and citizen-centric. The Ministry of Home Affairs, Government of India, has therefore invited Symbiosis Law School, Pune, to engage in research cum public consultation to review the criminal laws of the country and bring forth the necessary recommendations by engaging the public to improve them. In furtherance of the same, a team of Symbiosis Law School, Pune reviewed the relevant literature and collected data from more than 120 stakeholders including Judges, Lawyers, Academicians, Police, third gender, psychologist, researchers, experts, forensic officers, paralegal volunteers, journalists, social workers, sociologist, accused/suspects, victims and Prison Officials, in order to understand the gaps of the Criminal Legal Justice System.

6. Punekar News - <https://www.punekarnews.in/pune-virtual-panel-discussion-cum-public-consultation-on-transformation-of-criminal-justice-system-in-india/>



HOME / PUNE / PUNE: VIRTUAL PANEL DISCUSSION CUM PUBLIC CONSULTATION ON TRANSFORMATION OF CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDIA

Pune

Pune: Virtual Panel Discussion Cum Public Consultation On Transformation Of Criminal Justice System In India



Pune, October 21, 2020: Symbiosis Law School Pune, a constituent of Symbiosis International (Deemed University), hosted a Panel Discussion cum Public Consultation cum Public Consultation on 'Transformation of Criminal Justice System in India'. The 'virtual Panel Discussion cum Public Consultation' was conducted on 19th October.

The Government of India aims to make fundamental changes to the Indian Criminal Law framework and Criminal Justice System, in order to make it more accessible, affordable and citizen-centric. The Ministry of Home Affairs, Government of India, has therefore invited Symbiosis Law School, Pune, to engage in research cum public consultation to review the criminal laws of the country and bring forth the necessary recommendations by engaging the public to improve them. In furtherance of the same, a team of Symbiosis Law School, Pune reviewed the relevant literature and collected data from more than 120 stakeholders including Judges, Lawyers, Academicians, Police, third gender, psychologist, researchers, experts, forensic officers, paralegal volunteers, journalists, social workers, sociologist, accused/suspects, victims and Prison Officials, in order to understand the gaps of the Criminal Legal Justice System.

7. City Air News - <https://www.cityairnews.com/content/virtual-panel-discussion-cum-public-consultation-on-transformation-of-criminal-justice-system-in-india>

CITY AIR NEWS
DEDICATED TO THE FREEHOM JOURNALIST | STAFFER PERSPECTIVE

HOME NATION PUNJAB BUSINESS EDUCATION SPORTS LIFESTYLE ENTERTAINMENT OPINION ... Q

India / Education / Virtual panel discussion cum public consultation on Transformation of Criminal Justice System in India

Education

Virtual panel discussion cum public consultation on Transformation of Criminal Justice System in India

Ministry of Home Affairs, Government of India initiative

cityairnews · Oct 20, 2020 01:11

[Facebook](#) [Twitter](#) [In](#) [S](#) [P](#) [t](#) [e](#)



TUESDAY 27TH OF OCTOBER 2020 06:29:05 PM

POWER CUT IN LUDHIANA

The Guru Gyan Vihar Tassule under 66 kV model town grid, Ludhiana will remain off on 23-10-20 from 10:00 am to 04:00 pm due to urgent and necessary maintenance work.
Affected areas - Choti Jawaik, Parkash Nagar, Guru Gyan Vihar sector-2,3,4,5, Galleria Nagar, Vishal Nagar, some part of Kartar Singh Nagar (Phase-2).

FOLLOW US

[Facebook](#) [Twitter](#)
[Pinterest](#) [LinkedIn](#)
[YouTube](#) [Email](#)

RECOMMENDED POSTS



What is Bill of Lading: Definition & Importance

Launch ceremony of novella The

8. Business news this week - <http://businessnewsthisweek.com/business/virtual-panel-discussion-cum-public-consultation-on-transformation-of-the-criminal-justice-system-in-india-ministry-of-home-affairs-government-of-india-initiative/>

BUSINESS NEWS THIS WEEK

A LEADING BUSINESS NEWS PORTAL

HOME BUSINESS ENTREPRENEURSHIP ▾ WORLD NEWS HEADLINES ▾ PRESS RELEASES ▾ CONTACT US ▾

FEATURED RESOURCES

Reviews of the Best Gambling Apps for Real Money in India 2020, at sevenjackpots.com/casino-apps/

Visit <https://www.10cric.com/> Indias #1 operator for sportsbetting and casino games



Virtual Panel Discussion Cum Public Consultation on Transformation of The Criminal Justice System In India Ministry of Home Affairs, Government of India Initiative

October 21, 2020 Gouri Achary Business 0

Business News This Week > Business > Virtual Panel Discussion Cum Public Consultation on Transformation of The Criminal Justice System In India Ministry of Home Affairs, Government of India Initiative



Sarath Maneshinde Dr. Ahmed Tawfiq

Symbiosis Law School Pune, a constituent of Symbiosis International (Deemed University), hosted a Panel Discussion cum Public Consultation cum Public Consultation on 'Transformation of Criminal Justice System in India'. The 'Virtual Panel Discussion cum Public Consultation' was conducted on 19 October, 2020, from 3:00 pm to 7:30 pm.

SEARCH ...

9. Lokmat Marathi newspaper - <https://www.lokmat.com/national/big-news-movements-change-criminal-law-central-government-a580/>

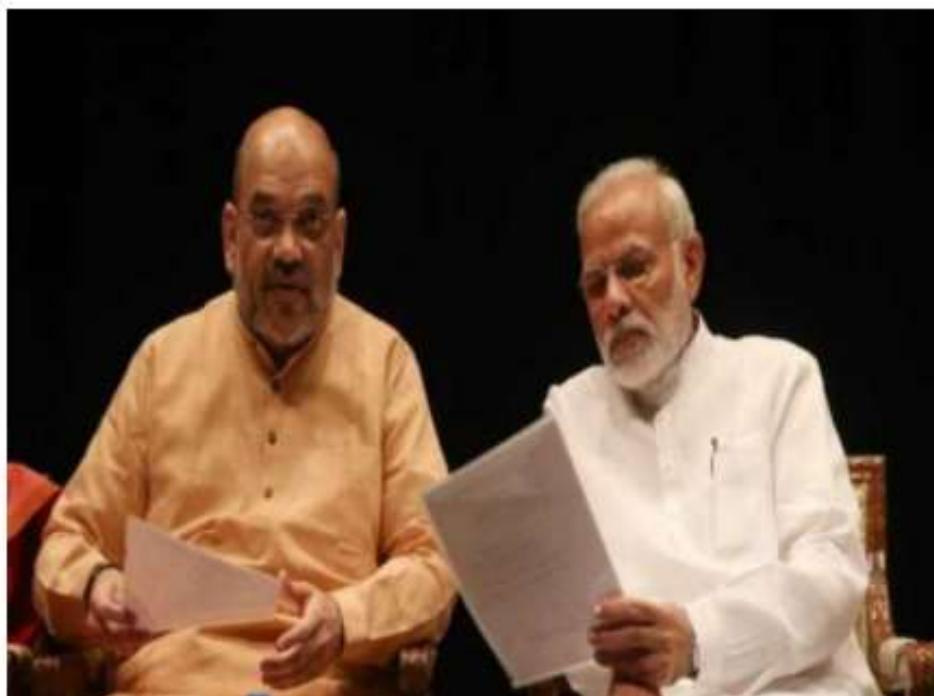
मोठी बातमी : केंद्र सरकार फौजदारी कायद्यात बदल करण्याची शक्यता; हालचाली सुरु

केंद्र शासनाने भारतीय फौजदारी कायद्यात परिवर्तन करण्यासंदर्भात हालचाली सुरु केल्या

By अॅनिलाइन लोकमत | Follow  | Published: October 21, 2020 02:11 PM | Updated: October 21, 2020 02:32 PM



A+ A-



मोठी बातमी : केंद्र सरकार फौजदारी कायद्यात बदल करण्याची शक्यता; हालचाली सुरु

ठळक मुद्दे

- फौजदारी कायद्याचा आडावा : पुण्यातील सिम्बायोसिस विधी मडाविद्यालयाकडून प्रक्रियेत सहभाग

पुणी : केंद्र शासनाने भारतीय फौजदारी कायद्यात परिवर्तन करण्यासंदर्भात हालचाली सुरु केल्या आहेत. प्रामुख्याने भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुराण कायदा, अमली पदार्थ सेवन विरोधी कायद्यात सावान्यांना आर्थिक दृष्टव्य परवणारे. आणि लोकाभिमुख बदल करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून ही प्रक्रिया सुरु

करण्यात आली असून या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सिम्बायोसिस विधी मडाविद्यालयाकडून फौजदारी कायद्याचा आडावा घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.

10. Sakal Marathi Newspaper - <https://www.esakal.com/pune/investigation-process-needs-change-increase-rate-sentencing-criminals-adv-ujjwal-nikam>

A medium shot of a man with dark hair and a prominent mustache, wearing thin-framed glasses and a dark suit jacket over a white shirt and tie. He is looking towards the right of the frame with a serious expression. In the background, several other individuals are visible, though they are out of focus. The setting appears to be an indoor event or press conference.

11. Pune Samachar - <https://punesamachar.com/latest-news/online-discussion-session-on-changes-in-indian-criminal/cid1546153.htm>

'भारतीय फौजदारी न्याय प्रणाली में परिवर्तन' पर ऑनलाइन चर्चा-सत्र

Thu, 22 Oct 2020 <



SYMBIOSIS LAW SCHOOL, PUNE

No.	Section/Rule	Problem	Recommendation	Justification:	Remark (If any)
1	Section 24, 25 and 25A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Amendment)	<ul style="list-style-type: none"> -Lack of quality prosecutors/Meritless prosecutors are not selected as private lawyers -Political interference -Lack of accountability -Low conviction rate -Lack of competency/exam skills are not tested while appointing the prosecutor 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Need to change the criteria for appointment of Prosecutors 2. Selection of prosecutors should be cross-verified after five years. Need to have independent body to review 3. Need to consider recommendations of judges/Judge/ Justice (High Court Judges, District Judge) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Date No. 95% No. 95% 2) Other Institute France/Germany 3) Review Jeff Model 	

SYMBIOSIS INTERNATIONAL (DEEMED UNIVERSITY)

पुणे।

सिंघायोसिस लॉ कॉलेज का आयोजन

प्राध्यायक लास्या व्याकरणम ने दूसरे चर्चासत्र का मूल्यांकात्मन किया। डॉ. शशिकला गुरुपुर, निदेशक एवं अधिष्ठाता, कानून शास्त्र सिंघायोसिस अंतर्राष्ट्रीय अभियंत विद्यापीठ ने सभी का स्वागत व विद्यार्थी की जानकारी दी। लॉ कॉलेज की उच्चनियेशक डॉ. बिंदु रोनाल ने चर्चासत्र में शामिल गणमान्यों का परिचय कराया। 'पुलिस अधिकारी व सरकारी वकील के बीच समन्वय से सजा दिताने की प्रक्रिया में बड़ीतरी' विषय पर हुई पैनल चर्चा में विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, एड. एस.के. जैन, एड. हितेश जैन, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भानुप्रताप बर्ग और वारिष्ठ क्राइम रिपोर्टर रोहित आठवले शामिल थे। 'गवाहों का संरक्षण विषय पर हुई चर्चा में मुंबई हाईकोर्ट की रिटायर जज डॉ. शालिनी फणसालकर जोशी, संशोधक और नीति सलाहकार आलोक अग्रवाल, अंड. लॉटीका सालागावकर, डॉ हरीश शेट्टी, (मानसोपचार विद), एड. हितेश जैन, (मुंबई उच्च न्यायालय) और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भानुप्रताप बर्ग ने हिस्सा लिया।

फौजदारी मामलों के पीड़ितों का संरक्षण और पुनर्वसन विषय पर हुई चर्चा में रिटायर जज डॉ. शालिनी फणसालकर जोशी, डॉ. एस.सी. रैना, (निदेशक, के.आप.आप.टी. भुवनेश्वर), एड. एस. के. जैन, सुनीत चौहान, निदेशक, पन.ए.एल.एस.ए, डॉ हरीश शेट्टी, (मानसोपचार विद), एड. लॉटीका सालागावकर शामिल हुए। मुकुदमा निपटारा के कानूनी प्रावधानों को दुरुपयोग विषय पर एड. एस. के. जैन, नीतीन कोडावले पाटिल, आईआरएस, एल. हितेश जैन, डॉ. डी. पी. सिंग, (समाजशास्त्र), टी.आप.एस.एस, एड. संपत बुतुसु, जनरल मैनेजर लीगल अंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, शेत हरीरा एल.एन.जी. ने हिस्सा लिया। जेल से छोड़ने के विषय पर न्यायमूर्ति शालिनी फणसालकर जोशी, एड. एस. के. जैन, एड. सुनीत चौहान, निदेशक, एन.ए.एल.एस.ए, अरविंद तिवारी, टी.आप.आप.आप.एस. डॉ. हरीश शेट्टी, (मानसोपचार विद) और एड. संपत बुतुसु, शामिल थे। 'सापबर एंड फौरेस्टिक' विषय पर हुई चर्चा में एड. सतीश मानेशीदे, डॉ. अरविंद तिवारी, भानुप्रताप बर्ग, डॉ. हेरोल. लीकोस्टा (सापबर फौरेस्टिक विद), एड. हितेश जैन शामिल थे।

TALK MAHARASHTRA

HOME पुणे मुंबई राज्य राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय विशेष दिल्हीओ

Home > News > शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यासाठी अमेरिकन तपास पद्धतेची गरज : उज्ज्वल निकम

शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यासाठी अमेरिकन तपास पद्धतेची गरज : उज्ज्वल निकम

By Tmadmin — On Oct 22, 2020

Total room visitors/participants: 156

Sl. No.	Section/Law	Problem	Recommendation	Justification	Remarks (Fanc)
1.	Section 24, 25 and 25A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Appointment)	<Lack of quality prosecution/Macrocum prosecutors are not selected as private lawyers +Political interference	1. Need to change the criteria for appointment of prosecutors. 2. Review: working of prosecutors should be cross-verified after few years. 3. Need to have independent body to review	1) Data: No. 95% No. 25% 2) Other systems: France/Germany 3) Review: MP Model	
	Appointment person with 7 years experience (Skills are not tested)	<Low Conviction rate	1.2. Need to consider Recommendation of Advise/ Justice (High Court Justice, District Judge)		
	Political interference: Zahira Hollandah v. State of Gujarat, 2004	<Lack of competitive exam: Skills are not tested while appointing the prosecutor			

Share 0

पुणे : भारतातील फौजदारी गुन्हांमध्ये आरोपींना होणाऱ्या शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यासाठी अमेरिकन तपास पद्धतीचा अवलंब करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत

ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी मांडले, 'भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीचे परिवर्तन' या विषयावरील ॲनलाईन चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.

केंद्र सरकारचा उद्देश केंद्रीय फौजदारी कायदेप्रणाली मध्ये परिवर्तन आणणेचा आहे. प्रामुख्याने भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि अमली पदार्थ सेवन विरोधी कायदा यामध्ये सामान्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे आणि लोकाभिमुख बदल करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सिंबायोसिस लॉ स्कूल पुणे येथे भारतीय फौजदारी कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी चर्चा सत्र भरवले होते.



Recording on Custom Live Streaming Service | Total non-video participants: 156 | Speaker View

Sr. No.	Section/Law	Problem	Recommendation	Justification	Annex (if any)
1.	Section 2A, 2B and 2BA of the Code of Criminal Procedure, 1973 [Appendment] Appointment person with 7 year experience [which are not valid]	-Lack of quality prosecutors/Most/more prosecutors are not talented as private lawyers -Political interference	I. Need to change the criteria for appointment of Prosecution I.1. Review working of prosecutors should be re-verified after few years. -Need to have independent body to review	I) Data Yes 95% No 5%	
	Political interference: <i>Zahra Rabbiah v. State of Gujarat 2004</i>	-Cost of accountability -Low Conviction rate -Lack of competitive exam skills are not tested while appointing the prosecutor	I.2. Need to consider recommendation of judge/ Justice [High Court Judge, District Judge]	II) Other System France/Germany III) Review MP Model	

SYMBIOSIS INTERNATIONAL (DEEMED UNIVERSITY)

भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीमधील परिवर्तन यावर ऑनलाईन चर्चासत्र

Posted By: Admin on: October 22, 2020 In: लोक्या बातम्या, देश-विदेश No Comments

[Print](#) [Email](#)

Share this post:



पुणे,(महाराष्ट्र ब्रेकिंग) - सिंबायोसिस अंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाच्या सिंबायोसिस विधी महाविद्यालय पुणे, इथे दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी द्वापारी ३ ते सायंकाळी ७.३० पर्यंत 'भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीचे परिवर्तन ' या विषयावरील ऑनलाईन चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.

केंद्र सरकारचा उद्देशे केंद्रीय फौजदारी कायदेप्रणाली मध्ये परिवर्तन आणणेचा आहे. प्रामुख्याने भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि अमली पदार्थ सेवन विरोधी कायदा यामध्ये सामान्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे आणि लोकाभिमुख बदल करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सिंबायोसिस लॉ स्कूल पुणे ला भारतीय फौजदारी कायद्याचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेत आमंत्रित केलेले आहे.

भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीमधील परिवर्तन यावर ऑनलाईन चर्चासत्र

— On Oct 22, 2020

ताज्या बात्या पुणे

Sr. no.	Section/Law	Problem	Recommendation:	Justification:	Remark (if any):
1	Section 24, 25 and 25A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Appointment)	<Lack of quality prosecutors/Most prosecutors are not talented as private lawyers >Political interference	1. Need to change the criteria for appointment of Prosecutors 2.1. Review: working of prosecutors should be cross-verified after few years. -need to have independent body to review	1) Data: Yes: 85% No: 15% 2) Other System: France/Germany	3) Review: MP Model
	Appointment person with 7 year experience (Skills are not tested)	<Lack of accountability <Low Conviction rate	3.2. Need to consider Recommendation of Judge/ Justice (High Court Judges, District Judges)		
	Political interference: Zahira Habibullah v. State of Gujarat 2004	<Lack of competitive exam- Skills are not tested while appointing the prosecutor			

SYMBIOSIS INTERNATIONAL (DEEMED UNIVERSITY)

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – सिम्बायोसिस अंतरराष्ट्रीय अभियांठाच्या सिम्बायोसिस विधी महाविद्यालय पुणे, इथे दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी दुपारी ३ ते सायंकाळी ७.३० पर्यंत ‘भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीचे परिवर्तन’ या विषयावरील आनलाईन चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.

केंद्र सरकारचा उद्घेश केंद्रीय फौजदारी कायदेप्रणाली मध्ये परिवर्तन आणणेचा आहे. प्रामुख्याने भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि अमली पदार्थ सेवन विरोधी कायदा यामध्ये सामान्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे आणि लोकाभिमुख बदल करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे ला भारतीय फौजदारी कायद्याचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेत आमंत्रित केलेले आहे.

15. YIN BUZZ (Sakal) - <https://www.yinbuzz.com/symbiosis-india-legal-system-reforms-online-discussion-31473>

YIN BUZZ 

होम वातमी राजकारण कॉलेजकड्हा इगमगाट करिअर LIVE TV  आणखी काही 

Home >> Blogs >> सिंबायोसिसतर्फे फौजदारी न्याय प्रणालीमधील परिवर्तनावर ऑनलाईन चर्चासत्र

सिंबायोसिसतर्फे फौजदारी न्याय प्रणालीमधील परिवर्तनावर ऑनलाईन चर्चासत्र

चैत्राली देशमुख | Friday, 23 October 2020



केंद्र सरकारचा उद्देशा केंद्रीय फौजदारी कायदेप्रणाली मध्ये परिवर्तन आणण्याचा आहे. प्रामुख्याने भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि अंमली पदार्थ सेवन विरोधी कायदा यामध्ये सामान्यांना अर्थिकदण्ड्या परवडणारे. आणि लोकाभिमुख बदल करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सिंबायोसिस लॉ स्कूलला भारतीय फौजदारी कायदाचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले.



भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीमधील परिवर्तनावर ऑनलाईन चर्चासत्र

पुणे: सिंबायोसिस अंतरराष्ट्रीय अभियंत विद्यार्थीठाच्या सिंबायोसिस विधी महाविद्यालयाच्या वर्तीने 'भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीचे परिवर्तन' या विषयावरील ऑनलाईन चर्चासत्राचे आयोजन नुकतेच करण्यात आले.

केंद्र सरकारचा उद्देशा केंद्रीय फौजदारी कायदेप्रणाली मध्ये परिवर्तन आणण्याचा आहे. प्रामुख्याने भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि अंमली पदार्थ सेवन विरोधी कायदा यामध्ये सामान्यांना अर्थिकदण्ड्या परवडणारे. आणि लोकाभिमुख बदल करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सिंबायोसिस लॉ स्कूलला भारतीय फौजदारी कायदाचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले.

सिंबायोसिस विधी महाविद्यालय पुणे ने संबंधित साहित्याचा आढावा घेतला आणि फौजदारी कायदातील त्रुटी समजून घेण्यासाठी न्यायाधीश, सरकारी वकील, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, पोलिस, निम सरकारी संस्था, प्रसारमाथमे, आणि कारगृह अधिकारी, यासह १२० हून अधिक फौजदारी प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभागीरादारांक इन माहिती गोळा केली.

प्राध्यापक लास्या व्याकरणम यांनी कार्यक्रमाचे सूक्ष्मसंचालन केले. डॉ. शशिकला गुरपूर, संचालिका आणि अधिष्ठिता, कायदा शाखा सिंबायोसिस अंतरराष्ट्रीय अभियंत विद्यार्थीठ यांनी स्वागत व विषयांची ओळख करून दिली.

पहिल्या पैनेलचे मोंडेरेशन डॉ. शशिकला गुरपूर तसेच डॉ. आनंदाराम शेळके, वरिष्ठ सहाय्यक प्राध्यापक यांनी केले. पोलिस अधिकारी व सरकारी वकील यांच्यात समन्वय ठेवून शिक्षणमधील अपेक्षित वाढ' या विषयावर पैनेलवर चर्चा झाली. यामध्ये विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, अॅड. एस.के. जैन, अॅड हितेश जैन, निवृत्त पोलीस अधिकारी आनुप्रताप बर्ग आणि पत्रकार रोहित आठवले सहभागी होते. संस्थेच्या उपसंचालिका डॉ. विंदु रोनाल्ड यांनी आभारप्रदर्शन केले.

16. PC Live news -

<http://pclive7.com/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%AB%E0%A5%8C%E0%A4%9C%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF-%E0%A4%AA/>

भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीमधील परिवर्तन यावर ऑनलाईन चर्चासत्र

Posted By: Admin on: October 23, 2020 In: देश, पिंपरी-चिंचवड, मुंगे, राज्य No Comments

[Print](#) [Email](#)

Sr. no.	Section/Law:	Problem:	Recommendation:	Justification:	Remark (If any):
1	Section 24, 25 and 25A of the Code of Criminal Procedure, 1973 [Appointment]	<Lack of quality prosecution/Maximum prosecutors are not talented as private lawyers ⇒ Political interference	1. Need to change the criteria for appointment of Prosecutors 1.1. Review: working of prosecutors should be cross-verified after few years. → need to have independent body to review	1) Data: Vec: 95% Raj: 05% 2) Other systems: France/Germany	
	Appointment person with 7 year experience (Skills are not tested)	<Lack of accountability	3) Review: MP Model		
	Political interference: Zahira Habibullah v State of Gujarat: 2004	<Low conviction rate <Lack of competitive exam- Skills are not tested while appointing the prosecutor	1.2. Need to consider Recommendation of Judge/ Justice (High Court Judges, District Judges)		

SYMBIOSIS INTERNATIONAL (DEEMED UNIVERSITY)

पुणे (Pclive7.com):- सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाच्या सिम्बायोसिस विधी महाविद्यालय पुणे, इथे दिनाक १९ अॅक्टोबर २०२० रोजी दुपारी ३ ते सायकाळी ७.३० पर्यंत 'भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीचे परिवर्तन' या विषयावरील ऑनलाईन चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. केंद्र सरकारचा उद्देश केंद्रीय फौजदारी कायदेप्रणालीमध्ये परिवर्तन आणेचा आहे. प्रामुख्याने भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि अमली पदार्थ सेवन विरोधी कायदा यामध्ये सामान्याना अर्थिक दृष्ट्या परवडणारे आणि लोकाभिमुख बदल करणे गरजेचे आहे. महणूनच भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सिवायोसिस लॉ स्कूल पुणे ला भारतीय फौजदारी कायद्याचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेत आमंत्रित केलेले आहे.

सिवायोसिस विधी महाविद्यालय पुणे ने संवेदित साहित्याचा आढावा घेतला आणि फौजदारी कायद्यातील त्रुटी समजून घेण्यासाठी न्यायाधीश, सरकारी वकील, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, पोलिस, निम सरकारी संस्था, प्रसारमाध्यमे, आणि कारागृह अधिकारी, यासह १२० हून अधिक फौजदारी प्रक्रीयेतील प्रत्यक्ष भागधारकांन माहिती गोळा केली. प्राध्यापक लास्या व्याकरणम यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. डॉ. शशिकला गुरुपूर, संचालिका आणि अधिकृता, कायदा शाखा सिम्बायोसिस अंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठ यांनी स्वागत व विषयाची ओलख करून दिली. आणि सिवायोसिस विधी महाविद्यालयाच्या परंपरेनंतर समाजातील कायदेशीर सुधारणीतील योगदानाबद्दल माहिती दिली. तसेच सदर कार्यक्रमाबद्दल विशेषत: संशोधन आणि फौजदारी प्रक्रियेबद्दल बोलल्या.

डॉ. विद्वा रोनाल्ड, उपसंचालिका, सिम्बायोसिस विधी महाविद्यालय, पुणे यांनी उपस्थित मान्यवरोचा परिचय करून दिला. या कार्यक्रमामध्ये ठराविक विषयानुसार सिम्बायोसिसच्या टीम ने सुचवलेल्या शिफारशीचा आढावा घेण्यात आला आणि प्रत्येक विषयानंतर ऑनलाईन प्रश्नावली पाठवून त्यावरी ऑनलाईन पद्धतीनेच मते घेण्यात आली.

फौजदारी न्याय प्रणालीमधील परिवर्तनावर ऑनलाईन चर्चासिंग

पुणे | प्रतिनिधि

केंद्र सरकारचा उद्देश केंद्रीय फौजदारी कायदेप्रणाली मध्ये परिवर्तन आणणोचा आहे. प्रामुख्याने भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि अमली पदार्थ सेवन विरोधी कायदा यामध्ये सामान्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे आणि लोकाभिमुख बदल करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सिंबायोसिस लॉ स्कूल पुणे ला भारतीय फौजदारी कायद्याचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेत आमंत्रित केलेले आहे. यादृष्टीने सिम्बायोसिस विधी महाविद्यालय येथे 'भारतातील फौजदारी न्याय प्रणालीचे परिवर्तन

या विषयावरील ऑनलाईन चर्चासिंगाचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले.

सिंबायोसिस विधी महाविद्यालयने संबंधित साहित्याचा आढावा घेतला आणि फौजदारी कायद्यातील त्रुटी समजून घेण्यासाठी न्यायाधीश, सरकारी वकील, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, पोलिस, निम सरकारी संस्था, प्रसारमाध्यमे, आणि कारागृह अधिकारी, यासह १२० हून अधिक फौजदारी प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष्य आणि अप्रत्यक्ष्य भागधारकांकडून माहिती गोळा केली. 'पोलिस अधिकारी व सरकारी वकील यांच्यात समन्वय ठेवून शिक्षेमधील अपेक्षित वाढ' या विषयावर पहिल्या सत्रात प्रवेलवर चर्चा झाली.